**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 :1086**

**दिनांक 29 जुलाई, 2015**

**ओपन एक्रियेज सिस्टम का प्रारंभ**

1086. श्री ए॰ विलियम रबि बर्नार्डः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ओपन एक्रियेज सिस्टम का प्रारंभ करने पर विचार कर रही है और नवीन अन्वेषण और अनुज्ञप्ति नीति (एनईएलपी) के अधीन तेल और गैस ब्लॉक की नीलामी के अगले दौर में उत्पादन भागीदारी संविदा (पीएससी) के फार्मूले को भी बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मौजूदा उत्पादन भागीदारी मॉडल में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और क्या नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने इस मॉडल के बारे में कुछ अभ्युक्ति की है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान)**

(क) और (ख): जी, हां। सरकार प्रस्‍तावित एक समान लाइसेंसिंग नीति (यूएलपी) के तहत ‘खुला रकबा’ प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है। इसके अतिरिक्‍त सरकार का मौजूदा उत्‍पादन हिस्‍सेदारी संविदा (पीएससी) मॉडल के स्‍थान पर राजस्‍व हिस्‍सेदारी संविदा मॉडल को शुरू करने का प्रस्‍ताव है।

(ग) और (घ): जी, हां। मौजूदा पीएससी मॉडल में कुछ प्रमुख मुद्दे/बाधाएं निम्‍नवत हैं:-

i. लागत कम रखने के लिए प्रचालक हेतु अपर्याप्‍त प्रोत्‍साहन।

ii. सरकार के हिस्‍से को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा अपेक्षित सतत तथा बारीकी से निगरानी जिससे प्रक्रियारत विलंब होता है और मध्‍यस्‍थम की स्‍थिति उत्‍पन्‍न होती है।

iii. वसूली योग्‍य लागतों का मूल्‍यांकन जिससे सरकार और संविदाकार के बीच विवाद होता है।

iv. प्रचालक को अपने पक्ष में निवेश गुणक का लाभ उठाने/इसे अपने अनुकूल बनाने के लिए अवसर प्रदान करना जिसके आधार पर लाभ हिस्‍सेदारी निर्धारित की जाती है।

 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने पाया है कि वर्तमान पीएससी पूंजीगत व्‍यय को कम करने के लिए निजी संविदाकारों को पर्याप्‍त प्रोत्‍साहन नहीं प्रदान करती जिससे कि निवेश गुणक को बढ़ाया जा सके (निवेश गुणक पर लाभ पेट्रोलियम का सरकार का हिस्‍सा निर्भर करता है)।